खंड

4

नब्बे के दशक के बाद से पुनरूत्थान

इकाई 9

फ्रेड रिग्ज़ का विकासशील देशों के लिए प्रशासनिक प्रतिमान 81

इकाई 10

तुलनात्मक लोक प्रशासन में बौद्धिक विकास 91

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 9 : फ्रेड रिग्ज़ का विकासशील देशों के लिए प्रशासनिक प्रतिमान

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 फ्रेड रिग्ज़ का विकासशील देशों के लिए प्रशासनिक प्रतिमान– पृष्ठभूमि

9.2.1 एग्रेरिया और इण्डस्ट्रिया प्रतिमान

9.2.2 फ्यूज़्ड–प्रिज्मैटिक–डिफ्रैक्टेड प्रतिमान

9.2.3 प्रिज्मैटिक प्रतिमान

9.3 प्रिज्मैटिक प्रतिमान की नकारात्मक प्रकृति

9.4 सारांश

9.5 संदर्भ एवं अन्य लेख

9.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- फ्रेड रिग्ज़ द्वारा विकासशील देशों के लिए दिए गए प्रशासनिक प्रतिमानों की पृष्ठभूमि का वर्णन कर सकेंगे;
- एग्रेरिया–इण्डस्ट्रिया प्रतिमानों से उन समाजों के मध्य, जो मुख्य रूप से 'औद्योगिक' है या 'कार्षिकी' हैं, में भेद कर सकेंगे;
- फ्यूज़्ड–प्रिज्मैटिक–डिफ्रैक्टेड प्रतिमानों की विशेषताएँ पर प्रकाश डाल सकेंगे; और
- प्रिज्मैटिक–साला प्रतिमान की विशेषताएँ तथा नकारात्मक प्रकृति का विश्लेषण कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में समकालीन सिद्धान्तकारों में सम्भवतः सर्वोच्च विद्वान फ्रेड रिग्ज़ है, जिसने प्रशासनिक प्रणालियों और उनके पयार्वरण के मध्य पारस्परिक क्रिया के वैचारिकीकरण के सम्बन्ध में गहन अध्ययन किया है। उनकी रुचि विकासशील और संक्रान्तिकालीन समाज में रही है। इस प्रकार के समाजों की 'प्रशासनिक पारिस्थितिकी' की व्याख्या हेतु ही उन्होंने 'प्रिज्मैटिक–साला' प्रतिमानों का निर्माण किया है।

इस इकाई में सर्वप्रथम रिग्ज़ के प्रारम्भिक 'एग्रेरिया' और 'इण्डस्ट्रिया' के प्रतिमानों के मूल घटकों का परिचय दिया गया है। त्पश्चात उनके 'फ्यूज्ड–प्रिज्मैटिक– डिफ्रैक्टेड प्रतिमानों के तात्त्विक लक्षणों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि रिग्ज़ तुलनात्मक लोक प्रशासन के उन लेखकों के लिए आदर्श है, जो गम्भीरतापूर्वक पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य में रुचि लेते हैं।

9.2 फ्रेड रिग्ज़ का विकासशील देशों के लिए प्रशासनिक प्रतिमान–पृष्ठभूमि

रिग्ज़ ने यह मत व्यक्त किया है कि वेबर का अधिकारितन्त्र का आदर्श रूप (Ideal Type) प्रतिमान, अपेक्षाकृत स्वायत्त प्रशासनिक प्रणाली की अपनी मान्यता के कारण, विकासशील राष्ट्रों के अध्ययन के लिये विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं है। क्यों कि इन राष्ट्रों में प्रशासनिक संरचनाओं की अन्य सामाजिक संरचनाओं से स्वायत्तता की वही मात्रा उपलब्ध नहीं है, जैसी कि विकसित समाजों में पाई जाती है। प्रशासनिक संरचनाएँ, जो सामाजिक प्रणाली के अन्य भागों के साथ घनिष्ठ और निरन्तर पारस्परिक क्रियाओं में संलग्न रहती हैं, विकासशील देशों में उच्चरूप से बहु–क्रियाकारी लक्षण ग्रहण कर लेती हैं। यह भी सम्भावना है कि ये संरचनाएँ पूर्णतया ''प्रशासनिक'' कार्य कम करें और गैर–प्रशासनिक कार्य अधिक। ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहाँ व्यवहार में ''व्यक्त'' (Manifest) प्रशासनिक कार्य सर्वथा अपेक्षित कर दिए जाएं। इस प्रकार की स्थितियों में, आदर्श रूप अधिकारितन्त्र के कठोर मानकों के आधार पर एक प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन करना अत्यधिक कठिन है। विकासशील राज्यों में वास्तविक अधिकारितन्त्रीय प्रणालियाँ वैध–विवेकपूर्ण प्रतिमान अथवा विशुद्ध पारम्परिक प्रतिमान से इतनी दूर होती है कि विशुद्ध द्विभागीकृत निर्मितयों की सहायता से उनका अध्ययन भ्रामक परिणाम ही प्रस्तुत करेगा। इसलिए, रिग्ज़ ने तर्क किया है कि 'आदिम' (Prijmative) और 'आधुनिक' (Modern) समाजों के सांरचनिक लक्षणों के मिश्रित रूप–युक्त समाजों के अध्ययन के लिये नवीन वैचारिक निर्मितयों की आवश्यकता है।

हालांकि, वेबर के अधिकारी–तन्त्र के विश्लेषण का मूल्यांकन प्रायः उस सारी प्रगति के दृष्टिकोण से किया जाता है, जो संगठन–सिद्धान्त, तन्त्रात्मक विश्लेषण, और वैकासिक सिद्धान्त ने लगभग पिछले तीन दशकों में किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह बलपूर्वक कहा जाए कि वेबर ने 'अधिकारी–तन्त्र' की व्याख्या ठीक उसी रूप में की है, जिसमें कि उन्होंने इस प्रत्यय को परिभाषित किया है। स्पष्टतया, इस परिभाषा में वर्तमान विकासशील राष्ट्रों की संस्थाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। अधिकारी–तन्त्रों के वैचारिकीकरण में उन समाजों पर दृष्टि अवश्य थी, जहाँ कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया न बहुत अधिक स्पष्ट थी न ही तीव्र, फलतः परिवर्तन के उन सभी सम्भावित परिणामों पर विचार नहीं किया गया, जो विकासशील सामाजिक प्रणालियों में होते हैं। वास्तव में, उस समय विकासशील राष्ट्र बहुत नहीं थे।

अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वेबर के विश्लेषण का मूल्यांकन करते हुए दो पूरक अभिगम अपनाये जा सकते हैः (1) वेबर के रीति–विज्ञान एवं लेखन काल के सन्दर्भ में उसके विचारों की परीक्षा करना, तथा (2) वेबर के विचारों को सामाजिक विश्लेषण की वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से देखना। द्वितीय अभिगम अपनाते समय यह स्वीकार करना चाहिए कि वेबर के विश्लेषण की अधिकतर सीमाएँ मूलरूप से निहित निर्बलताएं नहीं है, अपितु वर्तमान आवश्यकताओं के सन्दर्भ में ही उत्पन्न सीमाएं हैं। इसलिए, आवश्यकता यह है, कि त्वरित (Rapid) रूप से परिवर्तनशील अनुभवमूलक यथार्थता की चुनौती का सामना करने के लिए नई वैचारिक श्रेणियां बनाने हेतु प्रयत्न किये जायें। इस सन्दर्भ में लोक प्रशासन के अध्ययनों में पारिस्थितिक–वैकासिक परिप्रेक्ष्यों पर अधिक बल दिया गया है।

अब हम इन नई वैचारिक श्रेणियों पर चर्चा करेंगे।

9.2.1 एग्रेरिया और इण्डस्ट्रिया प्रतिमान

रिग्ज़ ने अपने एग्रेरिया–इण्डस्ट्रिया प्रतिमानों में उन समाजों के मध्य, जो मुख्य रूप से 'औद्योगिक' है या 'कार्षिकी' हैं, भेद किया है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक संक्रमण की पद्धतियों सहित वास्तविकताओं के वर्गीकरण और विश्लेषण के लिए परिकाल्पनिक (Hypothetical) श्रेणियों की प्रणाली प्रदान करने के लिये ये प्रतिमान बनाये गये थे। निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों से एग्रेरिया और इण्डस्ट्रिया के इन ध्रुवीय प्रतिमानों की निर्मिति में शाही चीन और समकालीन अमेरिका के समाजों ने क्रमशः आधार प्रदान किया है। तात्विक रूप से, ये प्रतिमान वेबर के पारम्परिक और वैध–विवेकपूर्ण प्राधिकार प्रणालियों की निर्मितियों के समान हैं। यह अन्तर अवश्य है कि जहाँ वेबर ने अपने प्रतिमानों की रचना में निगमनात्मक अभिगम का उपयोग किया है, वहाँ रिग्ज़ ने अपने प्रतिमानों को वैचारिक रूप प्रदान करने के लिये आगमनात्मक अभिगम का उपयोग किया है।

एग्रेरिया के मुख्य सांरचनिक लक्षण निम्न प्रकार हैं:

1. आरोपणात्मक (Ascriptive), विशिष्टात्मक (Particularistic) और विकीर्ण (डिफ्यूज्ड) पद्धतियों की प्रधानता;
2. स्थिर स्थानीय (Local) समूह और सीमित स्थानिक (Special) गतिशीलता;
3. अपेक्षाकृत सरल और स्थायी व्यावसायिक विशिष्टीकरण; तथा
4. विकीर्ण (Diffused) प्रभावों वाली, सम्मानपूर्ण स्तरण (Differential Stratification) की प्रणाली।

इसके विपरीत एक आधुनिक इण्डस्ट्रिया समाज को निम्नलिखित संरचनात्मक रूपों द्वारा लक्षित किया गया है:

1. उपलब्धि (Achievement), सार्वभौमिक (Universal), एवं विशिष्ट (Specific) मानकों की प्रधानता;
2. सामाजिक गतिशीलता की उच्च मात्रा, किन्तु अनिवार्यतया अनुलम्ब (Vertical) अर्थ में नहीं;
3. अन्य सामाजिक रचनाओं से पृथक्कृत सुविकसित व्यावसायिक प्रणाली;
4. व्यावसायिक उपलब्धियों की सामान्यीकृत पद्धतियों पर आधारित समतावादी वर्ग प्रणाली; तथा
5. 'संघों' की प्रमुखता, अर्थात्, क्रियात्मक रूप से विशिष्ट, अनारोपणात्मक (Non-Ascriptive) संरचना।

रिग्ज़ सहित कई विद्वानों ने यह अनुभव किया है कि एग्रेरिया और इण्डस्ट्रिया के ध्रुवीय प्रकार संक्रमणकालीन समाजों के अध्ययन में विशेष रूप से सहायक नहीं हैं। यद्यपि, रिग्ज़ ने एक मध्यवर्ती श्रेणी, ट्रांजिटिया, निर्मित की, किन्तु यह श्रेणी एग्रेरिया और इण्डस्ट्रिया के ध्रुवीय प्रकारों की अपेक्षा कम विकसित की गई। 'मिश्रित' प्रकार के समाजों के विश्लेषण के लिए आदर्श प्रकारों में विद्यमान यान्त्रिकी पर्याप्त न थी। आलोचकों का कथन है कि आधुनिक 'इण्डस्ट्रिया' प्रणाली स्वतन्त्र रूप से कभी भी विद्यमान नहीं रहती, अपितु सदैव ही अपने भीतर एग्रेरिया प्रणाली के तत्त्व लिये रहती है। इन प्रतिमानों में समाज की एकदिशात्मक गति– कृषि प्रधान स्थिति से एक उद्योग प्रधान स्थिति की ओर–की अवधारणा भी निहित है। साथ ही, एक अनुसन्धानकर्ता के दृष्टिकोण से इन प्रतिमानों की श्रेणियाँ अत्यधिक अमूर्त और सामान्य पायी गई हैं। इन प्रतिमानों की एक विशेष सीमा यह भी रही कि प्रशासनिक

प्रणालियों के विश्लेषण में इन्हें केवल पारिधिक स्थान ही प्रदान किया गया। स्वयं रिग्ज़ ने 1956 में एग्रेरिया–इण्डस्ट्रिया रीति–विज्ञान को त्याग कर एक नये 'फ्यूज्ड–प्रिज्मैटिक– डिफ्रैक्टेड' प्रतिमानों के वर्गीकरण की रचना की। अपनी कुछ सीमाओं के उपरान्त भी एग्रेरिया–इण्डस्ट्रिया रीति विज्ञान ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में पारिस्थितिकीय अध्ययनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

9.2.2 फ्यूज़्ड–प्रिज्मैटिक–डिफ्रैक्टेड प्रतिमान

बहु–कार्यात्मकता के विचार के अनुरूप सामाजिक संरचनाएं कार्यात्मक रूप से 'विर्कीण' (डिफ्यूज) हो सकती हैं (यदि वे बहुसंख्यक कार्यों को करती हैं), अथवा कार्यात्मक रूप से 'विशिष्ट' (स्पैसिफिक) हो सकती है। रिग्ज़ ने कार्यात्मक रूप से अपविस्तृत समाजों को 'फ्यूज्ड' और कार्यात्मक रूप से विशिष्ट समाजों को ' डिफ्रैक्टेड' दिया है। इन दो ध्रवीय प्रकारों का मध्यवर्ती समाज 'प्रिज्मैटिक' है। इस प्रकार फ्यूज्ड–प्रिज्मैटिक–डिफ्रैक्टेड प्रतिमानों का निर्माण आदर्श प्रकारों के रूप में किया गया है, जो किसी वास्तविक समाज में नहीं पाये जाते। यह अवश्य हो सकता है कि किन्हीं समाजों में इन आदर्श रूप प्रतिमानों की विशेषताएं स्थूल रूप से विद्यमान हों। इन प्रतिमानों का उद्देश्य अध्ययन–सामग्री को संकलित करना एवं एक स्वतः शोधात्मक प्रयोजन सम्पन्न करना है।

9.2.3 प्रिज्मैटिक प्रतिमान

पार्सन्स की समरूप परिवर्तियों (Pattern Variables) का उपयोग करते हुए रिग्ज़ ने परिकल्पना की है कि डिफ्रैक्टेड प्रणाली सार्वभौमिकतावाद (Universalism) और उपलब्धि–उन्मुखता की दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त करेगी, फ्यूज्ड प्रतिमान विशिष्टतावाद (Particularism) और प्रारोपण में उच्च स्थान पायेगा, तथा प्रिज्मैटिक प्रतिमान इन दोनों मापदण्डों का मध्यवर्ती होगा। रिग्ज़ ने समरूप परिवर्तियों की मध्यवर्ती श्रेणियां भी विकसित की हैं। इस प्रकार एक प्रिज्मैटिक समाज को 'वरणीयता सिद्धान्त' अथवा 'सिलैक्टिविज्म' (सार्वभौमिकतावाद और विशिष्टतावाद की मध्यवर्ती श्रेणी), 'सिद्धि' अथवा 'एटेनमैन्ट' (उपलब्धि और पारोपण की मध्यवर्ती श्रेणी), और 'मल्टिफंक्शनलिटी' (Multifunctionality) अथवा' बहु–कार्यात्मकतावाद' (कार्यात्मक विशिष्टता और कार्यात्मक अपविस्तृतता की मध्यवर्ती श्रेणी) द्वारा लक्षित किया गया है।

प्रिज्मैटिक समाज में सामाजिक संरचनाओं के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों और इस समाज के प्रशासनिक उपतन्त्र, जिसे रिग्ज़ ने "साला'' कहा है, के साथ उनकी परस्पर–क्रिया का अध्ययन ही रिग्ज़ के विश्लेषण का केन्द्र–बिन्दु है। फ्यूज्ड तथा डिफ्रैक्टेड समाजों की उन्होंने केवल रूपरेखा ही प्रदान की है, जो केवल उस सीमा तक प्रासंगिक है, जिस सीमा तक वह प्रिज्मैटिक समाजों के विश्लेषण में सहायक है। रिग्ज़ की मुख्य रुचि संक्रमणकालीन अथवा विकासशील समाजों में प्रशासनिक समस्याओं पर प्रकाश डालने में रही है।

रिग्ज़ के प्रिज्मैटिक–साला प्रतिमानों के आधारभूत लक्षणों में तीन विशेषताएं लक्षित की गई हैं: 'विजातीयता' (Heterogeneity), 'रीतिवाद' (Formalism), और 'अतिव्यापन' (Overlapping)।

आइये, अब हम इन तीनों विशेषताएं पर एकल रूप से वर्णन करें ।

- **विजातीयता (हैट्रोजिनीटी)**

  प्रिस्मैटिक समाज में विजातीयता की ऊंची मात्रा विद्यमान होती है। विजातीयता से अभिप्राय सर्वथा विभिन्न प्रकार की प्रणालियों, व्यवहारों और दृष्टिकोणों का समाज में एक ही समय में साथ–साथ विद्यमान होना है। फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड

लक्षणों का सहअस्तित्व एक अपूर्ण और असमान सामाजिक परिवर्तन का सूचक है और उसका परिणाम भी है। एक प्रिज्मटिक समाज में ''परिष्कृत'' बुद्धिजीवी वर्ग युक्त नागर क्षेत्र, पाश्चात्य शैली के कार्यालय, और प्रशासन के आधुनिक उपकरण विद्यमान रहते हैं। दूसरी ओर, ऐसे समाज में ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं, जिनका रूप–रंग और दृष्टिकोण पारम्परिक होता है; तथा ग्राम–प्रमुख, अथवा ''वृद्ध'' ही विविध राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, एवं सामाजिक भूमिकाओं का सम्पादन करते हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक प्रणालियों का भी लक्षण विजातीयता होता है। एक प्रिज्मैटिक समाज में, "साला'' आधुनिक कार्यालयों (Other), और परम्परागत दरबारों (Courts) अथवा कक्षों (Chambers) के साथ विद्यमान रहता है।

- **रीतिवाद (फॉर्मेलिज्म)**

'रीतिवाद' औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रभावशाली रूप से व्यवहृत मानकों तथा नियमों और यथार्थताओं के मध्य विसंगति अथवा सामंजस्य की मात्रा बताता है। सामंजस्य का स्तर इन तत्त्वों के मध्य ''यथार्थवाद'' (Realism) की मात्रा बताता है। इसके विपरीत इन दोनों के मध्य विसंगति रीतिवाद का प्रतिनिधित्व करती है। औपचारिकता और प्रभावशाली व्यवहार के मध्य जितनी अधिक विसंगति होगी, वह प्रणाली उतनी ही अधिक रीतिवादी मानी जायगी। फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड समाजों में अपेक्षाकृत यथार्थवाद की उच्च मात्रा होती है, जबकि एक प्रिज्मैटिक समाज रीतिवाद की उच्च मात्रा द्वारा लक्षित किया जाता है। प्रिज्मैटिक समाजों में वास्तविक शासकीय व्यवहार संविधियों के अनुरूप नहीं होता, यद्यपि सार्वजनिक अधिकारी कुछ कानूनों का शब्दशः अनुसरण करने पर आग्रह करते हैं। बहुधा वे कानूनों के प्राविधिक प्रावधानों और नियमों का अत्यन्त सावधानी के साथ अनुसरण करने का आग्रह करते हैं, जबकि, उसी समय अन्य विधानों–जो कि सामान्य नियमों और उद्देश्यों से सम्बन्ध रखते हैं–की उपेक्षा करते हैं। कार्यक्रम के लक्ष्यों पर बल देने की कमी, प्रशासनिक निष्पत्ति के मार्ग–दर्शक के रूप में सामाजिक सत्ता की दुर्बलता, और स्वेच्छानुसार प्रशासन के लिये भारी छूट ही रीतिवाद की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। रीतिवादी व्यवहार के लिए प्रोत्साहन अधिकारियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों अथवा विशिष्ट स्थितियों में उनको प्राप्त होने वाली अनुचित आय से मिल सकता है। इस प्रकार, रीतिवाद सामान्य रूप से अधिकारियों के भ्रष्टाचार की प्रक्रिया के साथ जुड़ जाता है।

रिग्ज़ के अनुसार यथार्थवाद–रीतिवाद द्विविभाजन का नीति परिणाम यह है कि एक डिफ्रैक्टेड समाज की प्रशासनिक संस्थानों में औपचारिक सुधार द्वारा प्रशासनिक व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, जब कि एक प्रिज्मैटिक समाज में, सम्भवतः इस प्रकार के सुधार केवल सतही प्रभाव डालते हैं। इसलिये, प्रिज्मैटिक समाजों में किन्हीं सांस्थानिक परिवर्तनों को लाने के पूर्व सार्वजनिक अधिकारियों में यथार्थवाद को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिये।

- **परस्पर–व्यापन (ओवरलैपिंग)**

विजातीयता और रीतिवाद से सम्बन्धित एक लक्षण है–'परस्पर–व्यापन,' जो एक डिफ्रैक्टेड समाज की औपचारिक रूप से विशिष्टीकृत संरचनाओं और फ्यूज्ड प्रकार की अविशेषित संरचनात्रों के सहअस्तित्व के परिमाण का बोधक है। उस सीमा तक, जिसमें संरचनाएं डिफ्रैक्टेड समाज में अपने 'व्यक्त'

कार्यों को करती हैं, पर्याप्त परस्पर व्यापन नहीं होता। इसी प्रकार, एक फ्यूज्ड समाज में, जिसमें प्रायः सभी प्रकार के कार्यों के लिए संरचनाओं का केवल एक विन्यास रहता है, परस्पर–व्यापन की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उस प्रकार के समाज में जो भी औपचारिक (Formal) होता है, वह 'प्रभावशाली' (Effective) भी होता है। दूसरी ओर, एक प्रिज़्मैटिक समाज में, यद्यपि नई अथवा आधुनिक सामाजिक संरचनात्रों की निर्मिति की जाती है, सार रूप में पुराने अथवा अविशिष्टीकृत संरचनाएं ही सामाजिक प्रणाली में प्रमुख स्थान रखती हैं। विवर्तित संरचनाओं के साथ सामान्य रूप से सम्बद्ध नये नियम और मूल्यों को केवल दिखावटी समर्थन दिया जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार पुराने मूल्यों के पक्ष में, जो कि अविशिष्टीकृत समाज के लिए उपयुक्त होती हैं, कार्य करते हैं। 'साला' (प्रशासनिक उपतन्त्र) में परस्पर–व्यापन के अस्तित्व की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासनिक निर्णय किस सीमा तक गैर–प्रशासनिक रूप से निर्धारित होते हैं, अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तथा अन्य तन्त्रों द्वारा।

एक प्रिज़्मैटिक समाज में परस्पर–व्यापन के कई उल्लेखनीय आयाम है। इनका वैचारिकीकरण, 'स्वजन पक्षपात;' 'बहुसांप्रदायिकतावाद' और 'क्लैक्ट्स' (Nepotism, Poly-communalism and Clects) की विद्यमानता; 'प्रिज्मैटिक अर्थव्यवस्था–'बाज़ार–कैण्टीन' प्रतिमान;' 'बहुनियात्मकतावाद' अथवा मतैक्य की कमी; और 'प्राधिकार का नियन्त्रण से पृथक्करण;' के रूप में किया गया है।

आइये, अब हम इन पाँचों विशेषताएं पर एकल रूप से वर्णन करें ।

क. स्वजन–पक्षपात (नेपोटिज्म)

एक डिफ्रैक्टेड समाज में पारिवारिक निष्ठा के विचार को सरकारी व्यवहार से पृथक रखा जाता है, जब कि एक फ्यूज्ड समाज में राजनीतिक–प्रशासनिक प्रणाली में आनुवंशिकता का लक्षण रहता है और इसलिए, रक्त सम्बन्धों अथवा पारिवारिक सम्बन्धों को भारी महत्त्व दिया जाता है। दूसरी ओर, प्रिज़्मैटिक समाज में नवीन औपचारिक संरचनाएँ पारिवारिक और रक्त सम्बन्धों पर अधिरोपित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में सार्वभौम मानकों की उपेक्षा कर दी जाती है। प्रशासनिक भर्ती स्वजन–पक्षपात (Nepotism) के आधार पर निर्धारित की जाती है। व्यक्त रूप से तो पारिवारिक सम्बन्धों के आधार पर प्रशासनिक नियुक्तियों का विरोध किया जाता है, किन्तु आचरण में इस व्यवस्था को अपनाया जाता है।

ख. बहु–सम्प्रदायवाद अथवा क्लैक्ट्स की विद्यमानता

डिफ्रैक्टेड समाज में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को जन संचार के लिये सक्रिय (Mobilise) किया जाता है। इस प्रकार के समाज में एक राष्ट्रीय समुदाय (National Community) होता है, जो कि अपने अभिजात वर्ग समूहों के साथ विद्यमान रहता है। दूसरी ओर, एक फ्यूज्ड समाज में, जन–संचार माध्यमों का अभाव रहता है, और इस प्रकार वहां जन–समवायन की मात्रा कम होती है। प्रत्येक ग्राम अथवा जन–जाति अपेक्षाकृत एक बन्द तन्त्र (Closed Systems) के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात् इन तन्त्रों की अपने पर्यावरण से नाममात्र की ही परस्पर–क्रिया होती है। इन दो ध्रवीय प्रकारों के मध्य में प्रिज्मैटिक समाज आता है, जहाँ अभिजातों की प्रतीक पद्धति (Symbol System) के साथ जन–समीकरण (Mass Assimilation) की गति सम्भवतः समवायन की गति की अपेक्षा मन्दतर होती है। यह स्थिति 'बहुसम्प्रायवाद' (Poly-communalism) की

स्थिति को जन्म देती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रजातीय धार्मिक और जातीय समूह परस्पर वैमनस्यपूर्ण सम्बन्धों में साथ–साथ रहते हैं।

इस प्रकार के बहुसम्प्रदायात्मक समाज में विविध 'हित समूहों' की सदस्यता अधिकांशतः बिरादरियों पर आधारित होती है। रिग्ज़ ने इन समूहों को क्लैक्ट्स (Clects) कहा है। क्लैक्ट्स में उपलब्धि–उन्मुखता, वरणीयतावाद, और बहुकार्यात्मकतवाद के लक्षण होते हैं। क्लैक्टस अर्ध–पारम्परिक प्रकार के अपेक्षाकृत अपविस्तृत कार्य करते है, यद्यपि उनका संगठन आधुनिक प्रकार का ही होता है। स्वाभाविक रूप से बहुसम्प्रदायवाद और क्लैक्टस, 'साला' के चरित्र को प्रभावित करते हैं। प्रिजमैटिक समाज में एक सार्वजनिक अधिकारी शासन की अपेक्षा, अपनी जाति के सदस्यों के प्रति सामान्यतया बृहत्तर निष्ठा विकसित कर लेता है। शासकीय पदों पर नियुक्तियों और नियमों एवं उपनियमों जैसे प्रशासनिक मामलों में, सर्वाधिक प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय असमानुपाती प्रतिनिधित्व एवं लाभ प्राप्त कर लेता है। तथापि, अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कभी–कभी सरकारी पदों पर भर्ती हेतु एक प्रकार का समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु एक अभ्यंश (Quota) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था विविध समुदायों में पारस्परिक वैमनस्य का कारण भी बन जाती है। इस प्रकार के वैमनस्य के परिणामस्वरूप विभिन्न शासकीय संस्थानों में कार्यरत विरोधी समुदायों के सदस्यों के मध्य असहयोग उत्पन्न होने की सम्भावनाएं बन जाती हैं।

कभी–कभी "साला'' अथवा इसका कोई उप–तन्त्र किन्हीं विशिष्ट 'क्लैक्ट्स'' के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित कर लेता है अथवा स्वयं एक 'क्लैक्टस'' की भांति कार्य करने लगता है। इन परिस्थितियों में 'साला'' मुख्य रूप से किसी विशिष्ट समुदाय के हित में कार्य करता है, किन्तु फिर भी यह उपलब्धि और सार्वभौम मानकों को दिखावटी समर्थन देना जारी रखता है। साला और क्लैक्ट के बीच इस सहयोग के फलस्वरूप साला के अधिकारी रिश्वत अथवा अन्य अवैध तरीकों से लाभ कमाते हैं। प्रिज्मैटिक व्यवहार का यह पक्ष प्रिज्मैटिक समाज की आर्थिक उप–प्रणाली के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है।

ग. प्रिज्मैटिक अर्थव्यवस्था–''बाज़ार–कैण्टीन'' (Bazaar-Canteen) प्रतिमान

एक डिफ्रैक्टेड समाज में मूल्य–निर्धारण तात्विक रूप से बाज़ार के मांग और पूर्ति तत्त्वों द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, फ्यूज्ड समाज में 'संघर्ष–घटक' (ऐरिना फैक्टर्स, वे घटक, जो शक्ति सन्तुलन, प्रतिष्ठा, और समेकता का निर्धारण करते हैं) अर्थव्यवस्था पर प्रमुख रखते हैं, तथा इसके परिणामस्वरूप मूल्य निर्धारण का प्रश्न कदाचित ही उठता है। प्रिज्मैटिक समाज में 'बाज़ार' और 'संघर्ष' तत्त्व परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा इस प्रकार ''मूल्य अनिश्चितता' की ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि जिसमें सामान्यतया एक वस्तु अथवा सेवा के लिये नियत मूल्य निर्धारित करना असम्भव होता है।

रिग्ज़ ने सार्वजनिक या लोक अधिकारियों और उनके असामियों के मध्य विनिमय सम्बन्धों का क्रेता और विक्रेता के सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। इस प्रकार प्रिज्मैटिक समाज में सार्वजनिक सेवाओं के लिए वसूल किया जाने वाला मूल्य सार्वजनिक सेवा और उसके असामियों के मध्य सम्बन्धों की प्रकृति के समनुरूप होता है। फलस्वरूप, स्वजनीय क्लैक्ट्स और प्रधान समुदाय के सदस्यों को घटी दर पर सेवाओं का विक्रय किया जाता है, और इसके विपरीत, अल्पसंख्यक समुदाय और बाहरी क्लैक्ट्स के लोगों से उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये ऊंचा मूल्य लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रिज्मैटिक समाज में आर्थिक संगठन एक अनुदान प्राप्त (Subsidised) कैण्टीन

के समान कार्य करते हैं तथा विशेष सुविधा प्राप्त समुदायों और राजनीतिक रूप से 'प्रभावशाली' व्यक्तियों को निम्नतर दरों पर वस्तुएं और सेवाएं बेची जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ये आर्थिक संगठन एक ''मातहत'' (ट्रिब्यूटरी) कैण्टीन के लक्षण रखते हैं तथा इस प्रकार 'बाह्य' समुदायों के सदस्यों से वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये अधिक मूल्य वसूल करते हैं।

प्रिज़्मैटिक समाज में मूल्य–अनिश्चितता एक ''बाज़ार'' जैसा वातावरण बनाती है, जिसमें वित्तीय व्यवहार के विभिन्न पक्षों, जैसे कर, शुल्क, छूट, और रिश्वत की मात्राओं के सम्बन्ध में सौदा होता रहता है। इस प्रकार के व्यवहार, समस्त वित्तीय प्रशासन, और विशेष रूप से आय–व्यय (बजट) निर्माण, लेखा विधि, और लेखा परीक्षण पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। मूल्य–अनिश्चितता सरकारी राजस्व संग्रह को भी दुर्बल करती है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक अधिकारियों को वेतन कम ही मिल पाता है। नियमित माध्यमों द्वारा कम पारिश्रमिक मिलने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अधिकारी अनुचित साधनों द्वारा अपनी आय बढ़ाने हेतु अभिप्रेरित एवं प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार शासकीय व्यवहार के मानकों पर आर्थिक उपतन्त्र का प्रभाव पड़ता है और यह मानक प्रिज़्मैटिक समाज के आर्थिक उपतन्त्र को भी प्रभावित करते हैं।

घ. बहुमानकवाद (Poly-Normativism) एवं मतैक्य का अभाव

एक प्रिज्मैटिक समाज में मानकों और नियमों के 'नये' विन्यास, पारस्परिक व्यवहार प्रणालियों के साथ–साथ विद्यमान रहते हैं। व्यवहार के औपचारिक और प्रभावी मानदण्डों के परस्पर–व्यापन के फलस्वरूप प्रिज्मैटिक समाज के अन्दर होने वाली सामाजिक परस्पर–क्रियाओं में आचरण के मानकों पर मतैक्य के अभाव के लक्षण पाये जाते हैं। 'बहुमानकवाद' अथवा 'मानकरहितता' की इस प्रकार की स्थिति का प्रभाव 'साला' पर पड़ता है, जहाँ कि सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक रूप से तो वस्तुनिष्ठा, सार्वभौमिकता, और उपलब्धि–उन्मुख मानकों के पालन का दावा करते है, परन्तु वास्तविक व्यवहार में, अधिकतम आत्मगत, आरोपणोन्मुख, और विशिष्टतावादी आचरण के मानकों का अनुसरण करते हैं। वे पद–स्थिति की परम्परागत कठोर पद–सोपानात्मक व्यवस्था का भी आदर करते हैं। ये अधिकारी दावा करते हैं कि वे अपने व्यवहार में विकास–युक्त मानकों का अनुसरण करते हैं, जब कि वास्तव में, वे परम्परागत व्यवहारों का अनुसरण ही कर रहे होते हैं। उनकी पश्चिमी मानकों के साथ–साथ ही, अपने सामाजिक अतीत का अनुसरण करने की अभिलाषा के कारण प्रशासनिक अधिकारी 'अनुकारी' (Imitative) व्यवहार–जिसका अभिप्राय दूसरों द्वारा किये गये व्यवहार की नकल करना है–विकसित कर लेते हैं। उन्होंने

एक प्रिज्मैटिक समाज के सार्वजनिक अधिकारियों का चयन–स्रोत सामान्य रूप से विशिष्ट समूहों तक ही प्रतिबंधित होता है। शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती की प्रणाली के बावजूद, सरकारी सेवाओं में प्रगति के अवसर, बड़ी मात्रा में, सेवा में वरिष्ठता एवं उच्चाधिकारी से मिलने वाले समर्थन पर ही निर्भर रहते हैं। एक सामान्य नागरिक भी 'साला' के साथ अपने सम्बन्ध में, बहुमानकीय होता है। एक ओर तो वह यह घोषणा करता है कि सरकारी व्यवहार में कठोर वैध–विवेकपूर्ण व्यवहार का पालन किया जाना चाहिऐ; तो दूसरी ओर, वह स्वयं के लाभ के लिये सरकारी नियमों की उपेक्षा करने को तत्पर रहता है।

ड. सत्ता का वितरणः प्राधिकार बनाम नियन्त्रण

साला के प्राधिकार तथा समाज के नियन्त्रण की संरचनाओं–जो बहु–सम्प्रदायवाद एवं बहु–मानकवाद पर आधारित हैं– के बीच परस्पर–व्यापन होता है। इस

प्रकार प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक संरचनाओं के अतिरिक्त, गैर–प्रशासनिक संरचनाओं द्वारा भी सम्पादित किये जाते हैं। इस प्रकार का परस्पर–व्यापन राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के पारस्परिक सम्बन्धों को प्रभावित करता है। सामान्यतया, प्रिज़्मैटिक समाज में, रिग्ज़ के शब्दों में, एक असन्तुलित राजतन्त्र पाया जाता है, जिसके अन्तर्गत राजनीतिक–प्रशासनिक तन्त्र पर प्रशासकों का प्रभुत्व होता है, इसके बावजूद कि राजनीतिज्ञों के पास औपचारिक रूप से नीति–निर्माण का अधिकार विद्यमान होता है। इस प्रकार एक डिफ्रैक्टेड समाज के प्रशासनिक तन्त्र की अपेक्षा साला में प्रशासकों की भूमिका अधिक प्रभावकारी होती है। अधिकारियों के हाथ में सत्ता के इस प्रकार के केन्द्रण का फल यह होता है कि जनता की आवश्यकतानों और आकांक्षाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम हो जाती है।

एक महत्त्वपूर्ण सीमा तक राजनीतिक नेताओं (प्राधिकार धारकों) का प्रभाव प्रशासकों को पारितोषिक अथवा दण्ड देने की उनकी क्षमता के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सम्भव है कि एक दुर्बल औपचारिक नेतृत्व सांगठनिक लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये प्रशासकों को उचित रूप से पारितोषिक देने में समर्थ न हो। ऐसी अवस्था में सम्भव है कि साला के प्रशासक स्वयं के हितों की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देने के लिए अभिप्रेरित हों। इस प्रकार साला के एक अधिकारी का व्यवहार एक ओर तो निर्णय–प्रक्रिया पर प्रभावशाली नियन्त्रण का हो सकता है, तो दूसरी ओर दायित्व–विहीनता का भी हो सकता है।

इन पाँचों विशेषताएं पर एकल रूप से वर्णन करने के बाद, आइये, अब हम प्रिज्मैटिक प्रतिमान का एक अवलोकन करें।

9.3 प्रिज्मैटिक प्रतिमान की नकारात्मक प्रकृति

प्रिज्मैटिक प्रतिमान की नकारात्मक प्रकृति सर्वप्रथम प्रिज्मैटिक समाज में विद्यमान व्यवहार के वर्णन के लिये रिग्ज़ द्वारा प्रयुक्त शब्दावली से ही स्पष्ट हो जाती है। प्रिज्मैटिक समाज की क्रियाशीलता को लक्षित करने के लिये रिग्ज़ ने 'मानकहीनता', 'कर्मकांडवाद' (Ritualism), 'अनुकरणशीलता' (Mimetic Behaviour), 'दानयुक्त व्यय,' 'बाज़ार कैण्टीन,' 'अनुदान प्राप्त कैण्टीन,' 'मिथ्यायें' (मिथ्स), 'दुहरी बात' (Double Talk), तथा 'हस्तक्षेप भावना' जैसे शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। निश्चित रूप से ये सभी शब्द प्रिज्मैटिक समाज के केवल नकारात्मक पहलुओं पर ही बल देते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि रिग्ज़ ने प्रिज्मैटिक समाजों को केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए चुना है, जो पश्चिम के मितव्ययता, कार्यकशलता, एवं नैतिकता के आदर्श मानकों का उल्लंघन करती दिखायी देती हैं। उन्होंने संक्रमणशील समाजों में पाये जाने वाले नैतिकता, कार्यकुशलता, एवं मितव्ययता के मानदण्डों द्वारा विकसित देशों में प्रचलित अकार्यकुशलता, अपव्यय, एवं अनैतिकता की स्थिति की कोई तुलना नहीं की। उनका प्रतिमान विकासशील देशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और प्रशासनिक उपप्रणालियों के निषेधात्मक पक्षों का ही विश्लेषण करता है। तार्किक रूप से एक अन्तर्निहित, आदर्शीकृत अमेरिकी तुलनात्मक सन्दर्भ में, प्रिज्मैटिक प्रतिमान एक मुख्यतयाः निषेधात्मक प्रकृति लिए उभरता है।

रिग्ज़ ने यह स्वीकारा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका डिफ्रैक्टेड प्रतिमान के प्रति समीप है, यद्यपि उसमें कुछ प्रिज्मैटिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। उदाहरणस्वरूप, अमेरिकी स्थानीय शासन में आज भी कानूनों व नियमों का उल्लंघन बड़ी मात्रा में होता है। किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा आपेक्षिक रूप से अन्य डिफ्रैक्टेड समाजों में

प्रिज्मैटिक व्यवहार के इस प्रकार के सन्दर्भ रिग्ज़ के विश्लेषण की योजना में केन्द्रीय स्थान नहीं रखते।

गतिविधि

भारतीय प्रशासन पारिस्थितिकीय अभिगम पर आधारित है। परीक्षण किजिए।

9.4 सारांश

पारिस्थितिकीय अभिगम तुलनात्मक लोक प्रशासन के रीति–विज्ञान से सम्बन्धित हैं। पारिस्थितिकीय अभिगम प्रशासनिक तन्त्र एवं उसके पर्यावरण के बीच गत्यात्मक सम्बन्धों का अध्ययन करता है। इस अभिगम का अधिकतम उपयोग रिग्ज़ ने किया है, किन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था के पर्यावरण की रचना पर विस्तृत वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाए तथा प्रत्येक पर्यावरणिक अवयव के प्रशासनिक तन्त्र के साथ क्रियात्मक सम्बन्धों का गहन विश्लेषण किया जाए।

9.5 संदर्भ

Arora, Ramesh K. 2021. Comparative Public Administration: An Ecological Perspective. New Delhi: New Age International.

Heady, Ferrel. 1995. Public Administration: A Comparative Perspective. New York. Marcel Dekker.

Riggs, Fred. 1964. Administration in Developing Countries: Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin.

Riggs, Fred. 1961. The Ecology of Public Administration. Bombay: Asia.

Sahni, Pradeep and E. Vayunandan. 2009. Administrative Theory. New Delhi: Prentice-Hall.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

इकाई 10 : तुलनात्मक लोक प्रशासन में बौद्धिक विकास

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 सुशासनः तुलनात्मक आधार

10.3 विश्व शासन सूचकांक

10.4 नव लोक प्रबंधनः तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

10.5 नव लोक सेवा दृष्टिकोण

10.6 विकासात्मक प्रबंधन

10.7 तुलनात्मक लोक नीति दृष्टिकोण

10.8 अग्रवलोकन

10.9 सारांश

10.10 संदर्भ

10.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- अंतर्राष्ट्रीय एवं तुलनात्मक प्रशासन में विभागीय भूमिका की चर्चा कर सकेगें;
- सुशासन सूचकांक सूची की व्याख्या कर सकेगें;
- तुलनात्मक लोक नीति का वर्णन कर सकेगें;
- नवलोक प्रबंधन की विशेषताओं का वर्णन कर सकेगें, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन को प्रभावित करते है; और
- नव लोक सेवा का वर्णन कर सकेगेंए जहाँ प्रशासनकों को नागरिकों को केन्द्र बिंदु में रखकर सारे काम को करना होता है।

10.1 प्रस्तावना

इस इकाई में 1970 के आरंभिक दौर के तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के विघटन के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा।

10.2 सुशासनः तुलनात्मक आधार

अच्छे शासन का आंदोलन 1992 में विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की पहल से आरंभ हुआ था और अब तक यह पूरे पश्चिमी और गैर–पश्चिमी देशों में फैल चुका है। इसके दर्शन तथा रणनीतियों को विकासशील और विकिसत देशों दोनों ने अपनाया है।

जब विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों व उप प्रणालियों की तुलना की जाती है, तब निम्न लिखित प्रश्न संबोधित होते हैः

1. प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थान तथा नागरिक समाज किस सीमा तक सुशासन व्यवस्था की लोक नीति तथा निर्णायक प्रणालियों में भागीदार होते हैं तथा उन्हें प्रभावित कर रहे हैं?
2. पुलिस द्वारा मानवाधिकारों, न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, व ईमानदारी का किस सीमा तक संरक्षण किया जा रहा है?
3. क्या सरकारी फैसले निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से लिए जा रहे हैं और उनका पालन हो रहा है?
4. क्या एक सुविकसित तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित है कि सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है?
5. शासन प्रणालियाँ नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति कितनी जवाबदेही व संवेदनशील है?
6. क्या समुदाय के सभी लोग टिकाऊ मानव–विकास के लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं?
7. शासन प्रणाली समग्रता व समानता सुनिश्चित कर पा रही है? क्या समाज का गरीब तपका विकास करने तथा अपने हितों को पूरा करने में समर्थ है?
8. सरकारी संस्थान कितने सक्षम हैं?
9. सरकारी संस्थान अपनी क्षमता का हरित संसाधनों के प्रति सतत उपयोग किस सीमा तक कर पा रहे हैं?

10.3 विश्व शासन सूचकांक

2008 में नई विश्व सुशासन फॉरम ने अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली से सम्बन्धित सूचकांक तैयार किये। इन सूचकांकों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में शासन प्रणालियों की संरचनाओं तथा कार्य निष्पादन का वार्षिक विवरण उपलब्ध कराना है। यह सूचकांक विभिन्न देशों की अलग–अलग शासन पद्धतियों की छवि पेश करते हैं तथा इन क्षेत्रों में आये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वैश्विक शासन की रूपरेखा तैयार करना, तथा उनके मात्रात्मक तथा गुणात्मक विकास का विवरण प्रस्तुत करना एक जटिल क्रिया है, जिसमें निरंतर सुधार तथा उनका निरीक्षण व मूल्यांकन करने की निरंतर आवश्यकता है।

इन सूचकांकों में शासन के मुख्य उद्देश्य 'सतत विकास लक्ष्यों' (Sustainable Development Goals (SDGs–एस डी जी) (2015-2030)) से जुड़े हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. शांति एवं सुरक्षा
2. लोकतंत्र तथा कानून व्यवस्था
3. मानवाधिकार एवं भागेदारी
4. स्थायी विकास
5. मानव विकास

इस प्रकार सुशासन का संबंध सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों से है। एस डी जी के संदर्भ में 179 देशों के आंकड़े एकत्रित किये गये तथा हर 5 संकेतकों के 13 उपसंकेतक बनाये गये।

ये संकेतक अत्यधिक उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर चुने गये थे। विश्व शासन सूचकांक (World Governance Index–WGI–डब्ल्यू जी आई) विभिन्न देशों में सुशासन की दृष्टि से एक अच्छा सूचकांक है और विभिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अच्छी रणनीति है। अच्छे शासन का सूचकांक (Good Governance Index–GGI–जी जी आई) भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश में शासन के स्तर का निश्चयन करना है।

यह राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन की पहलों तथा हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। मात्रात्मक डेटा पर आधारित यह सूचकांक राज्यों तथा केंद्रशासित क्षेत्रों को शासक की गतिविधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त रणनीतियों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने में विशेष रूप से सहयोगी है। सुशासन का सूचकांक दस कार्यात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित होता है– जैसे कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, जन–स्वास्थ्य, जन–अवसंरचना एवं उपयोगिताएँ, आर्थिक–शासन, समाज कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, तथा नागरिक केंद्रित शासन। हर वर्ष 25 दिसम्बर[1] को केंद्र व राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शासन प्रणालियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभिप्रेरित करता है। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन केवल अंतरराष्ट्रीय अध्ययन करने के लिए ही संकल्पित नहीं है, अपितु देश के अंतर्राज्यीय तथा अंतक्षेत्रीय व अंतर्विभागीय अध्ययन के लिए भी संकल्पित है। ऐसा करने से तुलनात्मक लोक प्रशासन अधिक व्यापक तथा अधिक सर्वग्राही बन जाता है।

10.4 नव लोक प्रबंधनः तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

1992 में अमेरिका में डेविड ऑस्बोर्न तथा टेड गेबलर की महत्वपूर्ण पुस्तक 'रिइवेंटिंग गवर्नमेंटः हाऊ द एंटरप्रेन्यौरशिप स्पिरिट इज ट्रांस्फोर्मिंग द पब्लिक सेक्टर' (Reinventing Government: How the Entrepreneurship Spirit is Transforming the Public Sector) प्रकाशित हुई थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को नौकरशाह कम और उद्यमशील अधिक होना चाहिए।

उपर्युक्त चुनौतियों को निभाने से एन पी एम (New Public Management–NPM) की एक सशक्त कार्य योजना बन जायेगी, जिससे तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे किये जा सकेंगे– क्षमता, अर्थ–व्यवस्था तथा प्रभाव परकता। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एनपीएम ने पहले से चले आ रहे काम के तरीकों, केंद्रीकृत नौकरशाही कार्य–पद्ध तियों को सिरे से नकार दिया है तथा इसके स्थान पर एक उत्प्रेरक, समुदाय आध ाारित, प्रतियोगितापरक, मिशन संचालित, परिणामोन्मुखी, ग्राहक संचालित उद्यमी, प्रतिबंधक, विकेंद्रीकृत, व बाजारोन्मुखी सरकार को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार सरकार की प्रशासन पद्धति नवीनता से भरी, सृजनकारी, दूरदर्शी, नीति–आधारित व नीतियों को लागू करने में विश्वास रखने वाली, तथा मूल्यांकन पूरक होती है। इसके लिए पर्याप्त रूप से निजी क्षेत्र की तकनीक को सरकारी क्षेत्र में लागू किये जाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों ने विकसित देशों से प्रशासनिक सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की हैं, इससे दुनिया के सभी देशों के बीच अपनी सरकारों को अधिक सक्षम और उद्यमपरक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हुई है।

[1] पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर

एन पी एम के लागू होने से अधिकतर देशों में निम्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं:

1. एन पी एम सुधारों का बाजारों, उदारीकरण, निजीकरण, तथा वैश्विकरण पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है।
2. नौकरशाही के विस्तार में कमी आई है, अनेक क्षेत्रों में नौकरशाही का प्रभाव को कम किया गया है।
3. नये सार्वजनिक उद्यमों की विकासशील देशों में भी स्थापना हुई है। अनेक राज्यों ने उद्यमों का पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से निजीकरण किया गया है।
4. सार्वजनिक क्षेत्रों तथा निजी क्षेत्रों की भागेदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली है।
5. अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक (लोक) तथा निजी क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा मिला है।
6. सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलने वाली कुछ सेवाओं को संविदात्मक आधार पर निजी कम्पनियों को दिया गया है।
7. बड़ी संख्या में विभागों तथा संस्थानों में नागरिक संहिताओं का निर्माण किया गया है तथा उन्हें लागू किया गया है। इन संहिताओं को सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता लाने तथा उनकी गति तेज करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।
8. सरकारी काम–काज में स्पष्टता, पारदर्शिता, तथा सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
9. परिणामपरकता तथा कार्यशीलता के परीक्षण के दायरे में रखते हुए विभिन्न सरकारी संस्थानों के काम–काज के प्रदर्शन अभिविन्यास पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, जो आउटकम (Outcome) बजट (परिणामोन्मुख बजट) तथा निष्पादन अंकोण द्वारा समर्थित होंगें।
10. पहल करने तथा पुरस्कृत करने की पद्धतियों को अनेक सरकारी उद्यमों तथा विभागों में लागू किया गया है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके।
11. सरकारी संस्थानों के विश्लेषण में अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करने तथा कम से कम निवेश करने की प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया गया है।
12. नागरिक सेवाओं में विशेषज्ञों की राय लेने को सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। उच्चतर सरकारी पदों पर प्रशासकों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संविदात्मक नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
13. लेखा, खरीदारी, भुगतान आदि क्षेत्रों के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी को विस्तृत रूप से लागू किया गया है। वास्तव में, प्रौद्योगिकी के स्तर पर सुधार तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वीकृत प्रदान की गई है।
14. सरकारी काम–काज के चुनिंदा क्षेत्रों में स्वायत्तता तथा कृत्रिम बौद्धिकता को प्रमुखता के साथ लागू किया जा रहा है।

उपर्युक्त प्रविधियों को अपनाने से दुनियाभर की शासन प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, तथा यह प्रमाणित हो रहा है कि शासन प्रणालियों का वैश्विकरण अब एक अनिवार्य आवश्यकता है।

10.5 नव लोक सेवा दृष्टिकोण

सार्वजनिक या लोक प्रशासन की भूमिका तथा संभवनाएँ पर रोबर्ट तथा जेनेट डेहार्ट एक अवधारणात्मक संरचना प्रस्तुत की है, जिसे नव लोक सेवा कहा जाता है, जो लोकतांत्रिक नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। सामुदायिक भूमिका, नागरिक समाज संस्थानों की भूमिका, तथा संगठनात्मक मानवतावाद के सिद्धांतों पर यह आधारित है। विचारधारा के समर्थक यह तर्क देते हैं कि लोक सेवक का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सहयोग करना है, जिससे वे अपने साझा हितों को समझ सकें।

डेनहार्ट (Denhardt) ने इस विचारधारा के कुछ ठोस पाठ निम्न प्रकार है, जो पारस्परिक रूप से समर्थन करती है:

1. सेवा करें, चलाने के जगह, यह शासन प्रणाली की सोच होनी चाहिए।
2. जनहित शासन प्रणाली का उद्देश्य है, ना कि शासन प्रणाली का उपोत्पादन
3. प्रशासकों को सैद्धांतिक आधार पर सोचना चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करना चाहिए।
4. सरकारी पहलों से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के साथ नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, उपभोक्ताओं की तरह नहीं।
5. लोक सेवकों का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम संविधान, संविधान प्रदत्त कानूनों, सामुदायिक मूल्यों, राजनैतिक मान्यताओं, व्यावसायिक प्रतिमानों, तथा नागरिक हितों के प्रति होना चाहिए।
6. एक आदर्श शासन प्रणाली लोगों को महत्व देती है, ना कि उसके उत्पादों को।
7. नागरिकोन्मुखी लोक सेवा को उद्यमशीलता से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

यहाँ एक प्रश्न उठता है–तुलनात्मक लोक प्रशासन का नई लोक सेवा से क्या संबंध है?

यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को देखें, विभिन्न देशों के संविधानों को देखें, विश्वभर के प्रमुख राजनैतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों को देखें, तो शासन के मानवतावाद पक्ष को पाते है। इनमें मानवाधिकारों की व्याख्या की गई है। दुनिया भर के सभी लोक सेवकों को उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है, जो बुलंद विचारों को व्यावहारिक वास्तविकताएं में परिवर्तित करते हैं। आजकल सकल घरेलू प्रसन्नता के उद्देश्य की प्राप्ति को अनेक देशों में सकल घरेलू उत्पाद से जोड़कर देखा जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक को दुनिया भर के प्रत्येक देश के नागरिकों की प्रसन्नता के संदर्भ में आंका जाता है। यह सोच लोक सेवकों पर बड़ी उत्तरदायित्व डालती है कि वे मानवीय और कल्याण केंद्रित बने। इस सोच ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है।

10.6 विकासात्मक प्रबंधन

पारंपरिक प्रबंधन मुख्यतः आंतरिक संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जब कि, विकास प्रबंधन अधिक से अधिक सामाजिक आधारित उद्देश्यों को प्राप्त करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार विकास मूलक प्रबंधन के तहत एक संगठन अपना संसाधन का उपयोग सामाजिक पद्धतियों को प्रभावित करने में करता है या इन पद्धतियों में प्रभावी हस्तक्षेप करता है, जिससे

सामुदायिक हितों के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस रणनीति में विभिन्न परस्पर सम्बंधित संगठनों के समन्वयन व सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अंतर संगठनीय समन्वयन व सहयोग में अपनी पूरी शक्ति लगायेगा। प्रभावी विकास प्रबंधन के लिए निम्न लिखित रणनीति व तकनीक लागू किये जाने की आवश्यकता है:

1. क्षमता निर्धारण तथा वैकल्पिक निवेशों का पता लगाना।
2. कर्मचारियों की तर्कसंगत पदोन्नति।
3. प्रभावी अभिप्रेरक तकनीक का उपयोग
4. प्रगतिशील व सक्षम नेतृत्व
5. आर्थिक एवं सामाजिक नीति विश्लेषण
6. साझा मूल्यों का नेटवर्क
7. प्रेरणादायक प्रबंधन
8. विभिन्न संगठनों के बीच विवादों को सुलझाना
9. लक्ष्यों पर आपसी बातचीत द्वारा सहमति प्राप्त करना
10. पद्धति परक प्रविधि अपनाये जाने पर जोर देना
11. कौशल विकास (संगठनात्मक विकास) द्वारा क्षमता निर्माण

यह स्पष्ट है कि विकास प्रबंधन और विकास प्रशासन के बीच अनेक आधारों पर संबंध है। यद्यपि विकास प्रशासन की संभावनाएँ विकास प्रबंधन की तुलना में अधिक व्यापक है। वास्तव में, विकास प्रबंधन निम्न या मध्यम स्तर पर होता है, जबकि विकास प्रशासन की सोच व क्षेत्र बड़े स्तर पर है। जहाँ तक पारिस्थितिकी की बात है, विकास–प्रबंधन विशेष रूप से सामाजिक वातावरण से सम्बंधित होता है, जबकि विकास प्रशासन बड़े स्तर पर पारिस्थितिकी पर आधारित होता है और पारिस्थितिकी में जनित राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, तथा प्रौद्योगिकी परिवेश को प्रभावित करता है और स्वयं प्रभावित होता है। निस्संदेह विकास प्रशासन तुलनात्मक रूप से लोक प्रशासन के लिए विकास–प्रबंधन से अधिक महत्व रखता है, परन्तु यह भी उतना ही सच है कि विकास प्रशासन की परिकल्पना प्रभावी विकास प्रबंधन के बिना संभव नहीं है।

10.7 तुलनात्मक लोक नीति दृष्टिकोण

पिछले कुछ दशकों में तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा तुलनात्मक सार्वजनिक नीति के रूप में सामने आई है। इसकी जड़े नये लोक प्रशासन में हैं, जो आरंभ से ही भाव–मूलक सार्वजनिक (लोक) नीति विश्लेषण पर जोर देता था। आरंभ में यह विचारधारा अमेरिका में सामने आई थी, कुछ पश्चिमी देशों में भी इसका अस्तित्व दिखाई पड़ा था। लोक प्रशासन पर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका 'द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिब्यू' (The Public Administration Review) में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों से सम्बंधित सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन, स्वरूप, प्रभाव, तथा प्रयोग पर अनेक लेख प्रकाशित हुए थे।

यद्यपि इनमें से अधिकतर लेख सामाजिक–आर्थिक सार्वजनिक नीतियों, विशेष रूप से अमेरिका के संदर्भ में थे। तुलनात्मक लोक प्रशासन के संदर्भ में लेखों को इस पत्रिका में लाने में लम्बा समय लगा। इस पत्रिका के मुख्य संपादक डेविड रोसेनब्लूम (David Rosenblum, 1991–96) बड़ी मुश्किल से इन लेखों को पत्रिका के अंकों में प्रकाशित

करने के लिए राजी हुए । 'अस्पा' की 'सिका' की पहल पर यह किया गया था।

सार्वजनिक नीति व विश्लेषण में विविध संकर राष्ट्रीय पहलों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक नीति उपागम को तुलनात्मक परिपेक्ष में प्रोत्साहन मिला।

विकासशील देश भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जल्द ही यह विचारधारा इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय हो गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग तथा दाता संस्थानों ने इसे बढ़ावा दिया। सुशासन तथा नव लोक प्रबंधन के संगम ने तुलनात्मक सार्वजनिक नीति उपागम के उद्भव व इसे बनाए रखने में एक उत्प्रेरक का काम किया।

तुलनात्मक सार्वजनिक नीति उपागम के कई पहलुओं की पहचान विचारक जामील ज्रीसत (Jamil Jreisat) ने कीः

- सार्वजनिक नीति प्रक्रिया
- नीति निर्धारण
- उप नीति निर्माण
- नीति कार्यान्वयन
- नीति मूल्यांकन
- मीडिया की भूमिका
- राजनैतिक नेताओं का प्रभाव
- विशिष्ट हित समूहों का प्रभाव
- निर्णय लेने के ढाँचे
  - तर्कसंगत प्रतिमान
  - वृद्धिशील प्रतिमान
  - सीमित तर्कसंगत प्रतिमान
  - सहमति निर्माण प्रतिमान
- सार्वजनिक नीति तथा प्रशासनिक कौशल
- संरचना, कार्य, तथा प्रशासनिक प्रणालियों पर सार्वजनिक नीतियों का प्रभाव

इस समय सार्वजनिक नीति की अवधारणा को दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपनाया है।

10.8 अग्रावलोकन

हम ऐसे कुछ रूझानों को सामने रख सकते हैं, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्वरूप प्रदान करते हैं।

1. आने वाले वर्षों में तुलनात्मक लोक प्रशासन और अधिक प्रबल होने वाला है तथा अपना और प्रभाव अंकित करने वाला है। चाहे किसी प्रशासनिक अध्ययन का वैज्ञानिक विश्लेषण सुगम बनाना हो या शासन प्रणाली के लिए एक प्रभावकारी संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, व्यवहारत्मक पहलुओं का अन्वेषण करना हो; इसकी भूमिका व उपयोगिता वास्तव में अत्यधिक रूप से बढ़ेगी।
2. विभिन्न देश विभिन्न प्रशासनिक आयामों जैसे संगठनों, प्रविधियों, प्रौद्योगिकियों, व्यावहारिक पद्धतियों, मानव संसाधन विकास, नगरीय शासन, ग्रामीण प्रशासन, नागरिक केंद्रित पहलों, तथा नैतिक संदर्भों आदि पर काम कर रहे हैं। यह

आशा की जाती है कि इन अध्ययनों से अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्सास्कृतिक प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक विकास के रास्ते निकाले जा सकेंगे, जिनके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक विश्लेषणों का सामान्यीकरण करने में सहयोग मिलेगा। इसके फलस्वरूप तुलनातमक लोक प्रशासन के क्षेत्र में नीचे दिये जा रहे महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकेंगे।

3. कुछ प्रख्यात दृष्टिकोण इस विषय के विश्लेषण में प्रचलित होंगे :

   क. संशोधित पारंपरिक तुलनात्मक लोक प्रशासन

   ख. मेक्स वेबर का नौकरशाही प्रतिमान और संकर राष्ट्रीय व संकर–सांस्कृतिक नौकरशाही प्रणालियों के कार्यों के बारे में वेबर उपरांत ज्ञान।

   ग. रिग्स का प्रिज्मेटिक प्रतिमान–व्याख्या, पुनव्याख्या, संशोधित, व संचालित।

   घ. एशिया, अफ्रीका, तथा लातिन अमेरिका की प्रशासनिक प्रणालियों की सामान्यीकृतता तथा विविधता पर शोध और पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, व जर्मनी आदि देशों की प्रशासनिक प्रणालियों पर नया अवतरण।

   - तुलनात्मक सार्वजनिक नीति विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया जाना।
   - प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन, तथा विकास प्रबन्धन की समस्याओं पर लगातार रूचि लेना।
   - रूस, चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, तथा जापान आदि देशों की क्षेत्रीय शासन प्रणालियां के अध्ययन में रूचि लेना तथा उन्हें महत्व देना।
   - विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तथा यू एन डी पी (UNDP) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त देशों की प्रशासनिक प्रणालियों के सुधार के लिए उठाये गये कदमों का विश्लेषण करना।

4. शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, लैंगिक (जेन्डर–Gender) न्याय, परिवहन, नगरीय विकास, ग्रामीण शासन आदि के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रशासनिक पद्धतियाँ का गहन अध्ययन।

5. नागरिक भागीदारी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, नागरिक संहिताओं, तथा उदार प्रशासन आदि के अध्ययन को तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत लाया जायेगा।

6. कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद असहिष्णुता, विरोध प्रदर्शन, सीमा विवाद, रक्षा प्रशासन, तथा विवाद प्रबंधन आदि से जुड़ी समकालीन समस्याओं पर भी तुलनात्मक विश्लेषण में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

7. तुलनात्मक लोक प्रशासन के कार्यात्मक परिभाषा, शोध प्रारूप, और वैचारिक निर्माण के निर्माण में होने वाले अनुसंधान कार्यों में लगातार वृद्धि होगी।

8. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जायेगा।

9. अनुसंधान सामग्री, प्रबंधों, पुस्तकों, तथा पत्र–पत्रिकाओं में तुलनात्मक लोक प्रशासन पर लिखे गये लेखों का प्रकाशन किया जायेगा तथा विषय के उत्थान हेतु ऑनलाइन इलैट्रोनिक उपकरणों (Online Electronic Gadgets) का उपयोग भी किया जायेगा।

10. सेवा गुणवत्ता पहल लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त सेवाओं की लागत को कम करती है तथा उनके गुणवत्ता को बढ़ाती है। भारत में उत्कृष्ट सेवा वितरण मॉडल 'सेवोत्तम' है, जिस में नागरिक घोषणा पत्र, शिकायत निवारण, आदि द्वारा नागरिको को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जातीं हैं।

11. सेवा गुणवत्ता पहल लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त सेवाओं की लागत को कम करती है तथा उनके गुणवत्ता को बढ़ाती है। भारत में उत्कृष्ट सेवा वितरण मॉडल 'सेवोत्तम' है, जिस में नागरिक घोषणा पत्र, शिकायत निवारण, आदि द्वारा नागरिको को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जातीं हैं।

12. पारदर्शिता व गुणवत्ता आई है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अब सारी सूचनाएँ पब्लिक डोमेन (Public Domain) में रखती हैं, जिससे नागरिको को शासन में भागीदार बनाया जा सकता है।

13. नव लोक सेवा (New Public Service) से नागरिक समाज को एक कार्यात्मक भूमिका मिली है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से अब सारी सूचनाएँ पब्लिक डोमेन में हैं, जिससे नागरिकों को शासन में भागीदार बनाया जा सकता है। बाजार संरचनाओं व राज्य की संस्थानों के बीच एक संतुलन होना अत्यावश्यक है। राज्य की संस्थानों को स्थानीय व स्वदेशी विकासीय अनुभव व क्षमता को बरकरार रखना अत्यावश्यक है।

10.9 सारांश

1990 के बाद सीपीए के क्षेत्र में बौद्धिक विकास प्रकरणों पर इस इकाई में विचार किया गया है। सिका (SICA), नव लोक प्रबंधन (NPM), विश्व शासन सूचकांक (WGI), तथा नव लोक सेवा (NPM) आदि महत्वपूर्ण पहल लोक प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय तथा तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में की गई। विश्वभर में लोक प्रशासनिक प्रणालियाँ, वर्तमान में, प्रबंधन प्रणालियों के प्रति अपनी समझ में वृद्धि कर सकते हैं; अंतर्राष्ट्रीय व तुलनात्मक लोक प्रशासन में शोध कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, विश्वव्यापी लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों की पहचान कर सकते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री को बढ़ावा दे सकते हैं, तथा विश्वभर में व्याप्त नवीन प्रशासनिक पद्धतियों के विकास में आने वाली विशेष समस्याओं को चिन्हित भी कर सकते हैं।

10.10 संदर्भ

Arora, Ramesh K. ed. 2011. Recent Perspectives in Public Administration. Jaipur: Aalekh.

Jriesat, Jamil. 2016. Comparative Public Administration and Policy. Philadelphia: Routledge.

Jriesat, Jamil. 2011. Globalism and Comparative Public Administration. Philadelphia: Routledge.

Medury, Uma. 2010. Public Administration in the Globalisation Era: The New Public Management Perspective. New Delhi: Orient Black Swan.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖